RAJYA SABHA

Thursday, the 9th March, 1989/ 18th Phalguna, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Performance of big industrial Houses on export front

*201. SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI VIRENDRA VERMA:†

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Committee to go into the factors responsible for the poor performance of the big industrial houses in the country on the export front;

(b) whether the Committee has submitted its report to Government; and

(c) if so, what are the salient features thereof and what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) No, Sir. However a panel has been set up to study the export performance of large industrial houses.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो पैनल उन्होंने बनाया है उसके कौन-कौन सदस्य हैं, कब वह पैनल बनाया गया था और कब तक उस रिपोर्ट को देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको आदेश दिया है?

श्री पी० आर० दास मुंशी : यह पैनल 29 दिसम्बर, 1984 के दिन हमने तय किया था । इस पैनल की अध्यक्षता एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री आफ कामर्स कर रहे हैं, इसके अन्दर जो सदस्य चुने गये हैं उसमें एक प्रतिनिधि . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : चुने गये हैं या नामिनेटेड है?

श्री पी० आर० दास मुंशी : नामिनेटेड हैं । उस कमेटी के अन्दर हैं एक डी०जी०टी० डी० का प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि सी० सी० आई० ए० जिसको हम चीफ कन्ट्रोलर; इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री का एकानामिक एडवाइजर, दो मिनिस्ट्री आँफ कामर्स के ज्वाएंट सेक्रेटरी उसमें हैं । इसका खास उद्देश्य यह है कि वह सब लार्ज हाउसेज के साथ बातचीत करें, उनसे रिपोर्ट मांगें और देखें कि कितना काम हुआ है । करीब-करीब उन लोगों ने 131 कंपनियों के साथ बातचीत कर ली है और बाकी काम अभी तक बाकी है। इस काम के खत्म होते ही, इस काम के खत्म होने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि पैनल ने क्या निश्चय किया है उनकी रिपोर्ट क्या है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मैंने यह पूछा था और अगर मंत्री महोदय बता सकें कि कब तक रिपोर्ट देने के लिए कहा था। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया । तो उत्तर में बता दीजिएगा अगर बता सकें ।

दूसरा प्रश्न यह है कि इससे पूर्व 1988–89 का जो बजट था उसमें एक्सपोर्ट के लिए अनेकों इंसेंटिव भारत सरकार ने दिए थे । उन इंसेंटिव के मातहत

क्या कोई गेन एक्सपोर्ट के मामले में सरकार को हुआ। अगर हां, तो कितना प्रतिशत हुआ इंसेंटिव दिए जाने का कारण यह था कि एक्सपोर्ट बढ़े तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं बिग फर्म्स ने, कम्पनियों ने जो आपका यह सुझाव था उस आधार पर किसी प्रकार का कोई सजेशन आपके पास भेजा है ?

श्री पी० आर० दास मुंशी : जहां तक उस समिति की रिपोर्ट की बात है, पैनल की रिपोर्ट की बात है, इसके लिए हम लोगों ने कोई डेट, तारीख निश्चित नहीं की है कि किस दिन के अन्दर काम खत्म करना है लेकिन हमने समिति को लम्बा समय दिया है साल के अन्दर सब बात करके जल्दी से जल्दी . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : साल के अन्दर यानी 31 मार्च ।

श्री सभापति : 31 दिसम्बर, 1989।

श्री पी० आर० दास मुंशी : इस साल के अन्दर जल्दी से जल्दी इन सबसे बात करके हम लोगों को सूचित करें कि क्या लार्ज हाउसेज का काम है । उसमें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है । जहां तक हमारे एक्सपोर्ट का सवाल है सरकार की नीति के कारण एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है, यह सबको पता है । मैं सिर्फ इतना ही सूचित करना चाहता हूं कि 1987–88 में एक्सपोर्ट पुराने साल के मुकाबले 25.3 प्रतिशत बढ़ गया है और उससे आगे 1988–89 में हम लोगों ने यह टारगेट फिक्स किया है कि यह 95 करोड़ हो जाये । हमें आशा है कि इस रिकार्ड को तोड़कर लोग करीब-करीब 20 हजार करोड़ तक इस मामले में पहुंच सकते हैं । इससे यह पता चलता है कि इस ओर हमने कितना इंसेंटिव दिया है । बल्कि इंसेंटिव न कहकर मदद कहना चाहिये और इसके कारण हम लोगों को अच्छा लाभ हो रहा है । मान्यवर, सदस्य ने पूछा कि सुझाव क्या है और उन पर हम लोगों ने काम किया है या नहीं, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने फिक्की के साथ सी०सी०आई०ए० के साथ, डी०जी०टी०डी० के साथ और जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल है, उनसे विचार करते हैं, पालिसी तय करने से पहले हम उनके सुझाव लेते हैं और उन सुझावों के साथ जब हम यह समझते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट का फायदा होगा तो हम उसी तरह से काम करते हैं । यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है कोई फिक्स नहीं है कि इस महीने में यह करना है । यह लगातार चालू है उनके सुझाव हम लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति जी, मैंने आपकी आज्ञा से दो स्पष्ट सवाल पूछे थे । एक तो यह कि 1988–89 के बजट में जो स्पेसेफिक इनसेंटिव एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने घोषित किये थे जिसके लिए आपने यह कहा कि 25.3 प्रतिशत आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है, मुझे मंजूर है । मैं यह कह रहा हूं कि जो इनसेंटिव एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने दिये थे उन इनसेंटिव्ज की वजह से कितने प्रतिशत एक्सपोर्ट बढ़ा है, केवल उन इन्सेंटिव्ज की मारफत । दूसरा मैंने पूछा था कि क्या किन्हीं दो बिग फर्मस ने टाटा, हिन्दुस्तान लीवर या और किसी ने आपके पास इस सिलसिले में कोई सुझाव भेजे हैं यदि भेजे हैं तो वे क्या हैं ?

श्री पी० आर० दास मुंशी : मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि सबने जो सुझाव हम को दिये हैं चाहे टाटा हो, हिन्दुस्तान लीवर हो, चैम्बर्स आफ कामर्स हो या फिक्की की ओर से सुझाव आए हों हम उनको ध्यान में रख कर ही हमने अपनी एक्जिम पालिसी तय की है जो कि पिछले साल पहली अप्रैल से लागू हुई। जहां तक इनसेंटिव देने का सवाल है बजट में हम जनरल ढंग से आम तौर से इनसेंटिव देकर एक वातावरण पैदा करते हैं और उसका फायदा भी हुआ है । यह फायदा कितना एक्सपोर्टर ले पाते हैं इसको देखने के लिए हर एक स्टेट में अपने-अपने ढंग से हम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काऊंसिल्ज के जरिये से नाप

करते हैं। मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि हमने बजट में जो वायदे किये हैं और जितना हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट था हम उससे भी आगे चल रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि जो बजट में इनसेंटिव हमने दिये हैं उनके कारण हम अपने लक्ष्य से अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह सब तो है।

श्री शान्ति त्यागी : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में और 1988-89 में दिसम्बर तक देश के जो 72 बिग बिजनेस हाऊसेज हैं इन्होंने कितने मूल्य का माल एक्सपोर्ट किया है और इम्पोर्ट किया है। क्या मन्त्री जी यह भी स्वीकार करेंगे कि देश में जो टाटा बिड़ला आदि जो बड़े परिवार हैं जो 72 फेमलीज हैं यह बेलगाम होती चली जा रही है और बावजूद इसके कि आपने उनको तमाम तरह की रियायतें दी हैं फिर भी यह एक्सपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं जो कि इनको करना चाहिये। क्या यह बात सही है कि हमारे देश में चूंकि इनका माल मंहगा बिकता है और इनको ज्यादा प्रोफिट होता है। इसलिए एक्सपोर्ट से भाग रहे है? अगर ऐसा है और आप यह बात स्वीकार करते हैं तो क्या उन पर कुछ लगाम डालने की आप कोशिश करेंगे, करेंगे तो वह क्या होगी?

श्री पी० आर० दास मुंशी : सभापति महोदय, अब तक अलग-अलग कम्पनी की अलग-अलग साल की स्पेसेफिक एक्सपोर्ट फिगर्ज हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग जो एक्सपोर्ट की फिगर्ज निकालते हैं वह हमारे ट्रेड की रिपोर्ट के अनुसार होती है। कस्टम के जरिए से सारे देश में जो एक्सपोर्ट होता है उस के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। जहां तक एक-एक हाऊस का अलग-अलग आंकड़ा देने का सवाल है हमने अब पहली बार यह निश्चय किया है कि उनको बैलेंसशीट के साथ उनका कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इम्पोर्ट हुआ उसको भी साबित करना होगा। अब से वह रिपोर्ट हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम लोग तय कर पाएंगे कि एक-एक कम्पनी ने, एक एक-ग्रुप ने कितना एक्सपोर्ट किया हैं और कितना इम्पोर्ट किया है। अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह फिगर्ज देना मुश्किल है। जहां तक हमारे जनरल इम्प्रेशन की बात है एक्सपोर्ट के सिलसिले में उनके योगदान के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि लार्ज हाऊसेज का एक्सपोर्ट के मामले में कोई हिस्सा नहीं है बल्कि यह कहना ठीक होगा कि जहां तक ट्रेडेबल चीजों का सवाल है जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनियां के बाजार में उसमें अगर हमारे लार्ज हाऊसेज ज्यादा कीमत होने की वजह से कम्पीट करने में उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो वह हमें सुझाव देते हैं कि हमें एक्सपेंशन का मौका दिया जाए ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट को स्केल डाऊन कर सकें। यह सब बातें हम सोच रहे हैं लेकिन जहां तक मार्केट की। एक्सेप्टेबिलिटी हैं, प्रोडक्ट की उसके आधार पर अगर कोई एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस अच्छा काम कर सकते हैं तो उसको हम मिसाल देते हैं लार्ज हाउस की उसको बता सकते हैं मोटीवेट कर सकते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारी जो सेल्फ रिलाएंट बनने की नीति है, अपने पैरों पर खड़ा होने की नीति हैं, डोमेस्टिक एरिया में थ्रस्ट बढ़ाने के लिए, इम्पोर्ट सबस्टीट्यूशन के जरिये से हम लोगों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। लेकिन जहां तक एक्सपोर्ट मोटिव, एक्सपोर्ट कल्चर पैदा करना है, इसके बारे में हम लोग कुछ साल पहले भी पीछे थे। अभी जो हमारे नये-नये कार्यक्रम सरकार की ओर से बने हैं इसके आधार पर एक्सपोर्ट का एक क्लाइमेट बन रहा हैं और इसमें लार्ज हाउसेज को अच्छे ढंग से शामिल करने के लिए हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : एक चीज माननीय सदस्य जो जानना

चाहते थे मैं इनको बता दूं कि जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने आंकड़े इकट्ठे किये हैं 581 बड़े हाउसेज के उनके हिसाब से 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में इनके इम्पोर्टस इनके आयात निर्यात से ज्यादा रहे।

श्री सभापति: आयात निर्यात से ज्यादा हैं?

श्री दिनेश सिंह: आयात ज्यादा हैं निर्यात कम रहे हैं।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, we find that the big houses imported more than what they exported. So, what is the actual share of big industrial houses on the export front of this country? Did the big industrial houses submit their plan of export to the Government? If so, what are the details thereof?

SHRI P. R. DAS MUNSHI: The long-term strategy of the corporate houses on the export front has been submitted and is being examined and looked into. Our Commerce Minister, Shri Dinesh Singhji, had a meeting with the large houses very recently on 11th February. Detailed discuussions were held as to how they should approach the long-term strategy of exports by the corporate houses. Insofar as the general performance is concerned, we have already stated that collectively the export front has been gaining ground. But selectively the porformance of the large houses has to be improved. The R.B.I. figures have already been quoted by the hon. Minister, Shri Dinesh Singhji. FICCI made a study of 100 large houses for the year 1984-85 and found that their performance on the export front was 4 per cent. The Economics Division of the Ministry of Commerce made a study of 100 large houses for the year 1986-87 and found that their performance was 2.4 per cent. The M.R.T.P. Commission made a study of 73 large houses for 1986-87 and found that their performance was 3.4 per cent. The ICIPI made a study of 264 houses for 1986-87 and found that their performance was 5.4 per cent. The Bombay Chamber made a study of 20 houses and found that the performance was 6.2 per cent. In general, we may say that certainly the large houses have yet to improve their export performance in the country and we are looking for it.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, in terms of dollar, the exports have increased only by 13 per cent. I do not remember the figure correctly. It is between 13 per cent and 17 per cent. But the imports have gone up. The import of edible oil has gone down by 50 per cent. What action does the Government propose to take to curb imports and increase exports.

SHRI P. R. DAS MUNSHI: Sir, many a time, the import control is not in our hands in the sense that we sanction as per the requirements of the various departments like food, steel and many other things. So far as the import price is concerned, the figure may look a little higher in view of the fact that the prices have gone up very high in the international markets. The quantity might be the same. In view of the fact that the prices have gone up, import figures look higher. We do control imports in terms of seeing that the import licence is being used properly or not. But the requirement of import is not in our hands. The requirement comes from various departments.

SHRI JAGESH DESAI: What I said was that the real exports have gone up only by 13 per cent in terms of the dollar. What action is the Government going to take to see that our exports are increased in real terms? At present, it is only 13 per cent and not 27 per cent.

SHRI P. R. DAS MUNSHI: Devaluation and depreciation of the rupee

in terms of the dollar is a well-known fact. We can only boost up our exports in a manner that in the hard currency areas we get a larger share of the market. The Ministry of Commerce and the Government as a whole are trying their best to penetrate more both in the E.C. countries and the United States so that we can have better sales in general currency areas to gain more. Besides the export incentives which have already been arranged, we cannot do much more. Within the knowledge of the GATT, whatsoever permissible, we can do. Beyond that, it cannot be possible. Certainly, in certain new sectors, to find new markets we are trying to penetrate where new areas can give us good dividends and good benefits, and that we are trying.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Chairman, Sir, we have to see that the question arises from the fundamental fact that the big houses are not contributing their might to the big effort of export promotion. Here, Sir, in another question—Question No. 207—in today's List of Business, we say that small-scale indurtries have been the main exporters this time. Those who are in the small-scale sector know that small-scale sector is the main exporter. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this Committee which has been constituted by him has been given a term of reference (a) to identify those areas and those things which are to be exported by these big houses and (b)—this is more important—in case they default in making that performance as recommended by that Committee, any penal action in whatever form—curtailment of import licence or any other form—has been given to this Committee as a term of reference.

SHRI DINESH SINGH: Sir, it is quite clear from the statistics that we have supplied that the share of the large houses in the export is very small. Now, there is a historical growth in this. Large houses have not only been engaged in exports, but they have also been engeged in meeting the domestic market. At one stage, encouragement had been given for import substitution and so on. So, there has been a historical growth of the industry more to cater to the domestic market rather than for export.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Colgate have invaded the small-scale sector. They have taken undue advantage to take over the small-scale sector. (*Interruptions*)

SHRI DINESH SINGH: Sir, now we are orienting them towards export. We feel they have the resources, they have the know-how, they have the organisation and, therefore, they should have a higher contribution in the export market. This is the whole effort in this. And that is why we are having a dialogue with them to see what is their difficulty if any, how we can remove their difficulties, how they can participate in a more meaningful manner in our export drive. Now this is the exercise that is going on. And the second point that the hon. Member mentioned was whether we are going to impose any quotas as such and whether there will be any punishment to defaulters. Imposition of quota is not an easy matter, and if you will recall, Sir, quotas have always created distortions. Therefore, we are not at this stage thinking in terms of any quotas. But we are thinking in terms of a voluntary contribution that they would make towards export. We should see how this works out before we think of any punitive action.

MR. CHAIRMAN: Question No. 202.

Settlement of overdrafts of States

*202. SHRI M.S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has stalled payments of overdrafts to some State Governments;